शुक्रवार
06 नवम्बर 2026
● देहरादून
● वर्ष 34
● अंक 285
● पृष्ठ 8
● मूल्य ₹ 1.00

34 साल से देहरादून का विश्वास

दून वैली मेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94

email: doonvalley_news@yahoo.com Website: dunvalleymail.com

डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

दून में गरजे अमित शाह

बोले- इस बार भाजपा का लक्ष्य 65 पार,कांग्रेस को जमकर घेरा

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के 26वें वर्ष के समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह देहरादून पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत भाजपा नेताओं ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड की धरती से आगामी विधानसभा चुनाव का सियासी शंखनाद करते हुए भाजपा की दोबारा सरकार बनने का दावा किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संबोधन के बाद जनसभा को संबोधित करने पहुंचे शाह ने सीधे कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि यहां से ऐसी आवाज उठनी चाहिए, जो राहुल बाबा तक पहुंचे कि उत्तराखंड में इस बार भी भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने जनसभा में मौजूद लोगों से मुट्ठी भींचकर विजय का संकल्प लेने और जय श्रीराम के नारे लगाने का आह्वान किया।

अमित शाह ने अपने संबोधन की शुरुआत लोगों का अभिवादन करते हुए राम-राम और नमस्कार से की। इसके बाद उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के संघर्ष को याद करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री और राज्य के निर्माता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने



कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने अलग राज्य के लिए लंबा संघर्ष किया। इस दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था में राज्य आंदोलनकारियों और युवाओं पर अत्याचार हुए। रामपुर तिराहा कांड सहित राज्य आंदोलन के दौरान हुए संघर्ष का उल्लेख करते हुए उन्होंने आंदोलनकारियों को नमन किया।

गृह मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी ने किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे संवारने का काम किया है। विकसित भारत की यात्रा में विकसित उत्तराखंड सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि प्रदेश गौरव, सिद्धि और संकल्प के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। गौरव उत्तराखंड राज्य के गठन का है, सिद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री

◆केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले- सूबे में बनेगी भाजपा की सरकार
◆परेड ग्राउंड से चुनावी हुंकार, मुट्ठी भींचकर लगवाए जय श्रीराम के नारे
◆अटल ने बनाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवार रहे उत्तराखंड

पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों की है।शाह ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य का जिक्र करते हुए कहा कि जब देश अपनी आजादी के सौ वर्ष पूरे करेगा, तब उत्तराखंड को विकसित राज्यों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करना है। इसके लिए अभी से संकल्प लेकर काम करना होगा। उन्होंने नई युवा पीढ़ी को देशभक्ति, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय गौरव के रास्ते पर आगे बढ़ाने की जरूरत भी बताई।

अपने संबोधन में अमित शाह ने उत्तराखंड की वीर परंपरा का उल्लेख करते हुए वीरांगना तीलू रौतेली और वीर माधो सिंह भंडारी को भी याद किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की पहचान उसकी वीरता, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति समर्पण से है। भाजपा सरकार इसी गौरवशाली विरासत को विकास के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है।

अमित शाह ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें ऐसा एक काम बताना चाहिए, जिसे उत्तराखंड की जनता याद रखती हो। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने उत्तराखंड की संरचना और विकास को रोकने का काम किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी के कार्यकाल में बने सड़क नेटवर्क और रमेश पोखरियाल निशंक के कार्यकाल में कुंभ के वैज्ञानिक आयोजन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक उत्तराखंड को मनीऑर्डर इकोनॉमी के भरोसे छोड़ दिया था, जबकि भाजपा ने प्रदेश में धन का सृजन करने वाली इंडस्ट्री स्थापित करने का काम किया है। सीमावर्ती क्षेत्रों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस कहती थी कि चीन अंदर आ जाएगा, लेकिन भाजपा सरकार ने सड़कों का निर्माण किया है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जब वह समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की बात करते हैं तो कुछ लोग इसे स्वीकार नहीं करते। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या देश में किसी को चार शादियां करने की अनुमति होनी चाहिए? उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अब कोई चार शादियां नहीं कर सकता और न ही तीन तलाक दे सकता है। अमित शाह ने दावा किया कि देश के 15 राज्यों में यूसीसी पर काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बिना किसी सिफारिश के 35 हजार युवाओं को नौकरी मिली है। प्रदेश में धर्मांतरण अब संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने कई विकास कार्य किए हैं। इनमें दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन, महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर जैसी उपलब्धियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन कार्यों का जिक्र करने लगेंगे तो सात दिन की भागवत कथा करनी पड़ेगी।

अमित शाह को काले झंडे दिखाने जा रहे दो छात्र नेता हिरासत में

हमारे संवाददाता

देहरादून। अमित शाह को काले झंडे दिखाने जा रहे दो छात्र नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे से पहले श्रीनगर गढ़वाल में पुलिस ने आइसा से जुड़े दो छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए छात्रों में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रसंघ के पूर्व उपाध्यक्ष शिवांक नौटियाल और वर्तमान विश्वविद्यालय प्रतिनिधि युवराज सिंह शामिल हैं। दोनों छात्र नेता अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय और मामले में कथित वीआईपी की भूमिका की जांच की मांग



को लेकर अमित शाह को काले झंडे दिखाने के लिए देहरादून जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें सुबह हिरासत में ले लिया।

छात्र नेताओं की हिरासत पर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और सीपीआई (एमएल) के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर पुलिस कार्रवाई को लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने का प्रयास बताया। मैखुरी ने कहा कि अमित शाह की सरपरस्ती वाली सरकार की पुलिस विरोध के स्वरों को खामोश करने में जुटी है। उन्होंने दोनों छात्र नेताओं की तत्काल रिहाई की मांग की।

मैखुरी ने कहा कि हिरासत और धरपकड़ से अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने समर्थकों और साथियों से छह नवंबर को सुबह 10 बजे देहरादून के गांधी पार्क पहुंचने और अमित शाह को काले झंडे दिखाने की अपील की है।गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छह नवंबर को देहरादून पहुंच रहे हैं। भाजपा की ओर से आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के तहत परेड ग्राउंड में पदयात्रा और जनसभा प्रस्तावित है। इसके अलावा शाह उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस निशान से अलंकृत करने के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे।

दून वैली मेल

संपादकीय

एआई के सपनों पर बाजार का हथौड़ा

कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई को दुनिया की अगली आर्थिक क्रांति बताने वालों के लिए अमेरिकी शेयर बाजार का ताजा झटका एक बड़ी चेतावनी है। जिस एआई के नाम पर कंपनियों के शेयर आसमान छू रहे थे, जिस तकनीक के भविष्य पर अरबों-खरबों डालर दांव पर लगाए जा रहे थे और जिस उम्मीद में निवेशक आंख मूंदकर पैसा लगा रहे थे, उसी एआई कारोबार की चमक पर अचानक सवाल खड़े हो गए हैं। अमेरिकी शेयर बाजार में आई भारी गिरावट ने तकनीकी कंपनियों के निवेशकों के भरोसे को हिला दिया है। एक ही कारोबारी सत्र में नैस्डैक-100 की बाजार पूंजी से करीब 2.3 ट्रिलियन डॉलर साफ हो गए। यह महज शेयरों की गिरावट नहीं, बल्कि एआई के नाम पर खड़ी की गई आर्थिक उम्मीदों और बाजार की अंधी दौड़ का आईना भी है। पांच नवंबर को अमेरिकी बाजार में जो हुआ, उसने वॉल स्ट्रीट के निवेशकों को सकते में डाल दिया। नैस्डैक कंपोजिट 5.5 प्रतिशत से अधिक टूट गया, एसएंडपी-500 में 4.4 प्रतिशत की गिरावट आई और डाउ जोंस करीब 3.4 प्रतिशत नीचे चला गया। एआई चिप बनाने वाली दिग्गज कंपनियां भी इस गिरावट से नहीं बच सकीं। एनवीडिया के शेयर करीब 9.3 प्रतिशत टूटे, जबकि एएमडी में 17 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। बाजार में बिकवाली का दबाव इतना व्यापक था कि तकनीक से जुड़ी कंपनियों के साथ दूसरे क्षेत्रों के शेयर भी इसकी चपेट में आ गए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिस एआई को दुनिया का भविष्य बताया जा रहा है, उसके नाम पर बाजार में इतनी घबराहट क्यों है? इसका जवाब सिर्फ राजनीतिक घटनाक्रम में नहीं, बल्कि एआई कारोबार की बुनियादी आर्थिक हकीकत में भी छिपा है। अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत के बाद डेटा सेंटरों के निर्माण और एआई उद्योग पर संभावित सख्त नियमन की आशंका बढ़ी है। डेटा सेंटर एआई व्यवस्था की रीढ़ हैं। इन्हें बनाने के लिए भारी पूंजी, बिजली, चिप और तकनीकी ढांचे की जरूरत होती है। यदि इनके निर्माण पर नियामकीय अड़चनें बढ़ती हैं तो एआई कंपनियों की विस्तार योजनाओं और उनसे जुड़े कारोबार पर असर पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन इस गिरावट का एक दूसरा और ज्यादा गंभीर पहलू भी है। दुनिया की बड़ी तकनीकी कंपनियां एआई पर जिस रफ्तार से पैसा खर्च कर रही हैं, उसके अनुपात में भविष्य का मुनाफा कितना होगा, यह अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। निवेशकों को अब सिर्फ भविष्य के सुनहरे सपने नहीं, बल्कि निवेश पर वास्तविक रिटर्न चाहिए। कंपनियां अरबों डॉलर के डेटा सेंटर बना रही हैं, महंगे चिप खरीद रही हैं और बिजली तथा सर्वर के बुनियादी ढांचे पर भारी खर्च कर रही हैं। सवाल यह है कि इस निवेश से कमाई कब और कितनी होगी? क्या एआई का बाजार इतनी तेजी से बढ़ेगा कि इस भारी खर्च की भरपाई हो सकेगी? यही अनिश्चितता अब शेयर बाजार के उत्साह पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। दरअसल, बाजार की सबसे बड़ी कमजोरी तब सामने आती है, जब किसी तकनीक की संभावनाओं को उसकी वास्तविक कमाई से कहीं आगे रखकर कंपनियों का मूल्यांकन किया जाने लगता है। एआई निश्चित रूप से मानव सभ्यता और अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखता है। शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, उद्योग, संचार और प्रशासन तक इसके प्रभाव दिखाई देने लगे हैं। लेकिन किसी तकनीक का उपयोगी होना और उससे जुड़ी हर कंपनी का शेयर लाभदायक होना दो अलग-अलग बातें हैं। तकनीक का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है, लेकिन उस भविष्य के नाम पर खड़े किए गए निवेश के मूल्यांकन हमेशा सही हों, यह जरूरी नहीं। यही वह बिंदु है जहां एआई की वास्तविक क्रांति और शेयर बाजार की काल्पनिक उम्मीदों के बीच अंतर करना जरूरी हो जाता है। इंटरनेट क्रांति के दौर में भी ऐसा ही हुआ था। इंटरनेट ने दुनिया बदल दी, लेकिन उस दौर में इंटरनेट के नाम पर खड़ी हुई तमाम कंपनियां बाजार में टिक नहीं सकीं। तकनीक बची, उसका विस्तार हुआ, लेकिन कई निवेशकों की पूंजी डूब गई। एआई के साथ भी यह खतरा मौजूद है। संभव है कि आने वाले वर्षों में एआई दुनिया की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण आधार बन जाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आज एआई के नाम पर ऊंचे मूल्यांकन वाली हर कंपनी कल भी बाजार की चहेती बनी रहेगी। इस घटनाक्रम का असर केवल अमेरिका तक सीमित रहने वाला नहीं है। वैश्विक वित्तीय बाजार एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। अमेरिकी बाजार में बड़ी गिरावट का असर दुनिया के दूसरे शेयर बाजारों, तकनीकी कंपनियों और निवेशकों की धारणा पर पड़ सकता है। भारत जैसे उभरते बाजार भी इससे पूरी तरह अछूते नहीं रह सकते। विदेशी निवेशकों का रुख बदलने, तकनीकी शेयरों में दबाव बढ़ने और वैश्विक निवेश धारणा कमजोर होने का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ सकता है। भारत के लिए यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था और एआई आधारित सेवाओं की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि इस एक दिन की गिरावट को एआई क्रांति का अंत मान लेना भी जल्दबाजी होगी। शेयर बाजार में गिरावट और किसी तकनीक की उपयोगिता का समाप्त होना एक बात नहीं है। एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है और आने वाले समय में इसका दायरा और व्यापक होने की संभावना है। लेकिन बाजार ने एक महत्वपूर्ण संदेश जरूर दिया है कि भविष्य की तकनीक के नाम पर वर्तमान की आर्थिक हकीकत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। निवेश की दुनिया में उम्मीद जरूरी है, मगर उम्मीद के साथ हिसाब-किताब भी जरूरी है। दरअसल, एआई के इस बाजार संकट ने दुनिया के सामने एक बड़ा आर्थिक सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हम वास्तव में तकनीकी क्रांति के दौर में निवेश कर रहे हैं या फिर भविष्य की संभावनाओं को आज ही मुनाफे में बदलकर देखने की जल्दबाजी कर रहे हैं? क्या कंपनियों की वास्तविक कमाई उनके बाजार मूल्यांकन को सही साबित कर पाएगी? और क्या दुनिया का ऊर्जा, पूंजी तथा तकनीकी ढांचा एआई की इस अंधाधुंध विस्तार यात्रा का बोझ उठा सकेगा? शेयर बाजार का मौजूदा संदेश साफ है। तकनीक पर भरोसा कीजिए, लेकिन उसके नाम पर आंखें बंद करके दांव मत लगाइए। एआई मानव भविष्य की बड़ी ताकत बन सकता है, मगर शेयर बाजार में किसी कंपनी का भविष्य सिर्फ उसके दावों से तय नहीं होता। वहां अंततः कमाई, कारोबार और आर्थिक बुनियाद ही असली कसौटी होते हैं। एआई की क्रांति जारी रह सकती है, लेकिन उसके नाम पर चल रही अंधी निवेश की दौड़ को अब बाजार ने ब्रेक लगा दिया है। सपनों की कीमत जब हकीकत से बहुत ज्यादा हो जाती है, तो बाजार इसी तरह हिसाब मांगता है।

चुनावी जंग को कांग्रेस तैयार, संगठन अब भी 'बीमार'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव का रण सजने लगा है। भाजपा ने लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए संगठन से लेकर बूथ स्तर तक मोर्चेबंदी तेज कर दी है। उत्तराखंड क्रांति दल उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुनावी मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है। दूसरी ओर कांग्रेस भी सत्ता में वापसी के दावे के साथ चुनावी तैयारी में जुटी है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की सक्रियता, संगठनात्मक बैठकों, जिला और विधानसभा स्तर पर नियुक्तियों तथा सरकार के खिलाफ आंदोलनों से पार्टी ने चुनावी माहौल बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। लेकिन कांग्रेस की इस तैयारी के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा है। क्या पार्टी वास्तव में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है या फिर उसकी तैयारी अभी भी बैठकों, बयानों और राजनीतिक घोषणाओं तक सीमित है?

कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती भाजपा सरकार नहीं, बल्कि खुद उसका संगठन बनता दिखाई दे रहा है। पार्टी के पास सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की लंबी फेहरिस्त है। बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, भर्ती घोटाले, महिला सुरक्षा, भू-कानून और अंकिता भंडारी प्रकरण जैसे सवालों पर सरकार को कठघरे में खड़ा करने का अवसर है। लेकिन सवाल यह है कि इन मुद्दों को गांव-गांव और बूथ-बूथ तक पहुंचाने वाला संगठन कहां है? राजनीतिक बयानबाजी और प्रेस कान्फ्रेंस से चुनावी जमीन तैयार नहीं होती। इसके लिए कार्यकर्ताओं की सक्रियता, स्थानीय नेतृत्व की स्वीकार्यता और मतदाताओं के बीच लगातार मौजूदगी जरूरी होती है।

प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल संगठन को चुनावी मोड में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिला और शहर इकाइयों के साथ विधानसभा स्तर पर जिम्मेदारियां तय करने की कवायद भी इसी रणनीति का हिस्सा है। पार्टी की कोशिश है कि चुनाव से पहले संगठनात्मक ढांचे को दुरुस्त किया जाए और कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाए। लेकिन संगठन की वास्तविक ताकत नियुक्तियों की सूची से नहीं, जमीन पर उसकी सक्रियता से तय होती है। कई विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के पास ऐसा मजबूत स्थानीय नेतृत्व नहीं दिखता, जो भाजपा के संगठित चुनावी तंत्र को सीधी चुनौती दे सके। कुछ क्षेत्रों में गुटीय खींचतान और पुराने नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई भी पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है।

◆सत्ता वापसी के दावे बड़े, लेकिन जमीन पर संगठन की पकड़ कमजोर
◆भाजपा ने बिछाई चुनावी बिसात, कांग्रेस अब भी है गुटबाजी के फेर में
◆सरकार के खिलाफ आंदोलनों से पार्टी ने चुनावी माहौल बनाने में जुटी

भाजपा की चुनावी रणनीति का सबसे मजबूत पक्ष उसका संगठन है। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं का नेटवर्क, शक्ति केंद्रों की सक्रियता, विस्तारक योजना और चुनावी प्रबंधन पर लगातार काम पार्टी को बढ़त देता है। भाजपा के सामने सरकार विरोधी नाराजगी और सत्ता विरोधी माहौल की चुनौती जरूर है, लेकिन संगठनात्मक स्तर पर उसकी तैयारियां कांग्रेस से अधिक व्यवस्थित दिखाई देती हैं। कांग्रेस के सामने चुनौती दोहरी है। उसे एक तरफ भाजपा सरकार के खिलाफ जनमत तैयार करना है तो दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं में यह भरोसा भी पैदा करना है कि पार्टी वास्तव में सत्ता में वापसी की स्थिति में है। जब तक कार्यकर्ता खुद जीत को लेकर आश्वस्त नहीं होगा, तब तक वह मतदाताओं को भी भरोसा नहीं दिला पाएगा।

उत्तराखंड कांग्रेस की राजनीति में गुटबाजी कोई नया विषय नहीं है। वरिष्ठ नेताओं के बीच राजनीतिक वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा और टिकटों को लेकर संभावित दावेदारी चुनाव के नजदीक आते ही तेज होने की आशंका है। पार्टी के सामने सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी कि वह चुनाव से पहले सभी प्रमुख नेताओं को एक मंच पर ला पाती है या नहीं। यदि टिकट वितरण के दौरान असंतोष खुलकर सामने आया तो भाजपा को कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का फायदा मिल सकता है। कांग्रेस के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों के चयन से पहले ही विधानसभा क्षेत्रों में दावेदारों और संगठन के बीच समन्वय स्थापित किया जाए। केवल चुनाव के समय एकजुटता का संदेश देने से बात नहीं बनेगी।

कांग्रेस के लिए राहत की बात यह है

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

यूकेडी का 'चौका' भाजपा-कांग्रेस 'आउट'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा में अभी वक्त है, लेकिन सियासी मैदान में उत्तराखंड क्रांति दल ने ऐसा दांव चला है, जिसने भाजपा और कांग्रेस दोनों को चुनावी तैयारी के मोर्चे पर चुनौती दे दी है। सत्ता की लड़ाई में उलझे दोनों राष्ट्रीय दल अभी संगठन और रणनीति को धार देने में जुटे हैं, वहीं राज्य आंदोलन की राजनीतिक विरासत का दावा करने वाले यूकेडी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। भाजपा और कांग्रेस के टिकटों पर अभी चर्चाओं और दावों का दौर है, जबकि यूकेडी ने प्रत्याशियों के नाम सामने रखकर अपनी मंशा साफ कर दी है।

इसे महज उम्मीदवारों की घोषणा मानना भूल होगी। दरअसल, यूकेडी इस बार 2027 के चुनाव को अपनी राजनीतिक वापसी के अवसर के रूप में देख रहा है। पार्टी का दांव है कि उत्तराखंड की जनता को भाजपा और कांग्रेस के बीच सत्ता के अदल-बदल से आगे एक मजबूत क्षेत्रीय विकल्प दिया जाए। राज्य गठन के आंदोलन से निकली पार्टी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती उस राजनीतिक विरासत को चुनावी जनसमर्थन में बदलने की है, जिसे वह लंबे समय से अपना आधार बताती रही है। यूकेडी की पहली सूची ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा जरूर पैदा की है। भाजपा और कांग्रेस जहां अभी चुनावी समीकरणों, संगठनात्मक बैठकों और संभावित उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में हैं, वहीं क्षेत्रीय दल ने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुनावी बढ़त लेने की कोशिश की है। इससे पार्टी को उम्मीदवारों को अपने क्षेत्रों में सक्रिय करने, स्थानीय मुद्दों पर अभियान चलाने और मतदाताओं के बीच पहचान बनाने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।

यह रणनीति भाजपा और कांग्रेस के लिए भी एक संदेश है कि क्षेत्रीय राजनीति को पूरी तरह नजरअंदाज करना अब आसान नहीं होगा। खासकर उन क्षेत्रों में जहां स्थानीय पहचान, मूल निवास, भू-कानून, रोजगार और पहाड़ के विकास जैसे मुद्दे मतदाताओं को प्रभावित करते हैं।

◆उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर राष्ट्रीय दलों को दी चुनौती
◆2027 में तीसरे विकल्प की दस्तक से बदलेगा अब सियासी गणित
◆भाजपा और कांग्रेस के टिकटों पर अभी चर्चाओं और दावों का दौर

भाजपा 2027 में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी संगठन चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए सरकार के खिलाफ मुद्दों को धार देने में लगी है। दोनों राष्ट्रीय दलों की लड़ाई के बीच यूकेडी ने तीसरे विकल्प की जमीन तैयार करने की कोशिश की है। यूकेडी की चुनौती यह है कि क्या वह भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ पैदा हो रही नाराजगी को अपने पक्ष में समेट पाएगा? क्या राज्य आंदोलन के दौर की राजनीतिक चेतना को फिर से जगाया जा सकेगा? क्या पार्टी केवल क्षेत्रीय अस्मिता की बात करने के बजाय रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और पहाड़ की अर्थव्यवस्था पर ठोस विकल्प दे पाएगी?

उत्तराखंड क्रांति दल के पास राज्य गठन आंदोलन की ऐतिहासिक विरासत है। लेकिन इस विरासत को चुनावी सफलता में बदलने में पार्टी अब तक अपेक्षित कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। संगठनात्मक बिखराव, नेतृत्व के अंतर्विरोध और चुनावी स्तर पर कमजोर प्रदर्शन ने उसकी राजनीतिक ताकत को सीमित किया है। यही वजह है कि इस बार उम्मीदवारों की जल्द घोषणा के साथ पार्टी को अपने संगठन और नेतृत्व की एकजुटता भी साबित करनी होगी। राज्य गठन के 26 वर्ष बाद भी पहाड़ में पलायन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, शिक्षा के संकट और स्थानीय संसाधनों पर अधिकार जैसे सवाल कायम हैं। यूकेडी इन्हीं मुद्दों को अपनी राजनीति का आधार बनाने की कोशिश कर रहा है। पार्टी के लिए यह चुनाव केवल विधानसभा में सीटें बढ़ाने का अवसर नहीं, बल्कि अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस हासिल करने की निर्णायक लड़ाई भी है।

उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर यूकेडी ने निश्चित रूप से चुनावी चर्चा में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। लेकिन राजनीति में शुरुआती चौका मैच जीतने की गारंटी नहीं होता। भाजपा के पास मजबूत संगठन और सत्ता की ताकत है,

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का प्राथमिकता से हो समाधान

अल्मोड़ा(आरएनएस) उत्तराखंड राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष एवं राज्य मंत्री एके सिकन्दर पंवार ने विकास भवन सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर सफाई कर्मचारियों के हितों, कल्याणकारी योजनाओं और स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सफाई कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। बैठक में पंवार ने कहा कि सफाई कर्मचारी समाज में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके अधिकारों, हितों और कल्याण के प्रति सभी संबंधित विभागों को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का समय पर निस्तारण सुनिश्चित करने और शासन की ओर से संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र कर्मचारियों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रयास करने को कहा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सफाई कर्मचारियों या किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे समाज का साझा दायित्व है। आमजन में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए संबंधित विभाग आपसी समन्वय से जनजागरूकता गतिविधियां संचालित करें और नागरिकों को अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित करें। आयोग के उपाध्यक्ष ने स्वच्छता और सफाई कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े मामलों में सभी विभागों को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

एमबीपीजी हल्द्वानी ने जीती अंतर महाविद्यालय कबड्डी ट्रॉफी

नैनीताल(आरएनएस)। मुख्य अतिथि कुलपति प्रो. सतपाल सिंह बिष्ट रहे। प्रतियोगिता में रामनगर के खिलाड़ी ट्रायल के रूप में शामिल हुए, जबकि डीएसबी परिसर नैनीताल, राजकीय महाविद्यालय हल्द्वानी, इंदिरा प्रियदर्शिनी गर्ल्स कॉलेज हल्द्वानी, राधे हरि महाविद्यालय काशीपुर, बाजपुर, खटीमा, एसबीएस रुद्रपुर और एमबीपीजी कॉलेज की टीमों ने भाग लिया। नॉकआउट आधार पर खेले गए सेमीफाइनल में एमबीपीजी और एसबीएस रुद्रपुर ने फाइनल में जगह बनाई। टूर्नामेंट में राष्ट्रीय खिलाड़ी मनमोहन बसेरा, मोनिका, राजेंद्र नेगी, विमल, प्रवीण सिंह राणा ने रेफरी और टेक्निकल की भूमिका निभाई। शिक्षा संकायाध्यक्ष प्रो. ललित तिवारी ने खिलाड़ियों को नशे के खिलाफ शपथ दिलाई। कुलपति प्रो. बिष्ट ने कहा, कि पंजाब-हरियाणा की तरह कुविवि की छात्राएं भी खेल के दम पर पुलिस विभाग में उच्च पदों तक पहुंचे, विश्वविद्यालय इसके लिए हर संभव मदद करेगा। शारीरिक शिक्षा विभागाध्यक्ष डॉ. संतोष कुमार ने बताया, कि यह चयन ट्रायल भी था। लगभग 11० खिलाड़ियों में से 12 का चयन होगा, जो दिसंबर में एमजीएम यूनिवर्सिटी मोहाली में होने वाले नॉर्थ जोन टूर्नामेंट में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस मौके पर कुलसचिव प्रो. रितेश साह, परिसर निदेशक प्रो. संजय पंत, छात्र संघ अध्यक्ष भानुप्रताप सिंह चौहान, सचिव कमल कार्की मौजूद रहे।

विधानसभा चुनाव के लिए कार्मिकों का डाटाबेस तैयार

हरिद्वार(आरएनएस) विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2०27 की तैयारियों के तहत मतदान और मतगणना कार्मिकों का डाटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों और शिक्षण संस्थानों को कार्मिकों का अद्यतन विवरण पांच नवंबर तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड के निर्देशों के अनुपालन में जनपद के केंद्र और राज्य सरकार के सभी सरकारी व अर्द्धसरकारी विभागों, कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों तथा शिक्षकों का विवरण जुटाया जा रहा है। इसका उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान और मतगणना कार्मिकों की व्यवस्था सुनिश्चित करना है।उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित प्रारूप-1 और प्रारूप-2 के भाग 2/1, 2/2, 2/3 और 2/4 में शुद्ध, स्पष्ट, त्रुटिरहित और अद्यतन सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। विवरण ई-मेल या हार्ड कॉपी के माध्यम से जिला सूचना विज्ञान केंद्र, हरिद्वार में जमा कराया जा सकता है। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि निर्धारित समय तक कार्मिकों का डाटा उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आश्वस्त हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन व लेख में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो *सांध्य दैनिक दून वैली मेल* के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

–प्रबंधक विज्ञापन

तीसरा मोर्चा:भाजपा-कांग्रेस की उड़ी 'नींद'

◆सूबे के 14 संगठनों को एक मंच पर लाने की मुहिम
◆2027 में टूटेगा भाजपा-कांग्रेस का सियासी चक्रव्यूह
◆आंदोलन की जमीन पर सियासी पुनर्जन्म की तैयारी
◆क्षेत्रीय राजनीति को नया जीवन देने की है कोशिश

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड की सियासत में अब तक भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रहे सत्ता के खेल में तीसरा खिलाड़ी भी ताल ठोकने की तैयारी में है। विधानसभा चुनाव 2027 की रणभेरी बजने से पहले उत्तराखंड क्रांति दल ने ऐसा दांव चला है, जिसने प्रदेश की राजनीतिक चर्चाओं को नया मोड़ दे दिया है। भाजपा और कांग्रेस अभी उम्मीदवारों के चयन, चुनावी रणनीति और संगठनात्मक समीकरणों में उलझे हैं, वहीं यूकेडी ने 16 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर अपनी चुनावी मंशा साफ कर दी है। संदेश साफ है- इस बार क्षेत्रीय राजनीति केवल चुनावी खानापूर्ति नहीं करेगी, बल्कि सत्ता के खेल में हिस्सेदारी मांगने मैदान में उतरेगी।

यूकेडी की यह पहल महज प्रत्याशियों की सूची जारी करने तक सीमित नहीं है। पार्टी की निगाह भाजपा-कांग्रेस के बीच बने उस राजनीतिक द्विध्रुवीय ढांचे को तोड़ने पर है, जिसने राज्य गठन के बाद से उत्तराखंड की राजनीति को अपने घेरे में रखा है। राज्य आंदोलन की कोख से निकला क्षेत्रीय दल अब उसी आंदोलन की राजनीतिक विरासत को फिर से भुनाने की तैयारी में है। सवाल यह है कि जिस दल ने उत्तराखंड बनाया, क्या वह अब उत्तराखंड की सत्ता में अपनी खोई हुई जगह वापस हासिल कर पाएगा?

यूकेडी ने 16 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर राष्ट्रीय दलों को यह संकेत देने की कोशिश की है कि चुनावी तैयारी में वह पीछे नहीं है। पार्टी ने फाइव लेयर सिस्टम के तहत प्रत्याशियों के चयन की बात कही है। सूची में अनुभवी चेहरों के साथ युवाओं को भी जगह दी गई है। पिथौरागढ़ से काशी सिंह ऐरी, द्वाराहाट से पुष्पेश त्रिपाठी, कर्णप्रयाग से आशीष नेगी, देवप्रयाग से पूरण सिंह कठैत, प्रतापनगर से पंकज व्यास, जागेश्वर से दिनेश कुंजवाल, सल्ट से प्रताप सिंह, टिहरी से डीडी पंत, कपकोट से वरुण चंदोला, काशीपुर से प्रदीप चंद, नानकमत्ता से कैलाश सिंह पांगती, रामनगर से भुवन चंद्र, देहरादून कैंट से राजेंद्र सिंह नेगी, खानपुर से रितु कंडियाल जुयाल, धनोल्टी से चंदन सिंह राणा और राजपुर से देव चंद उत्तराखंडी को मैदान में उतारने की घोषणा की गई है।

प्रत्याशियों की समय से पहले घोषणा के पीछे पार्टी की मंशा राष्ट्रीय दलों से अलग चुनावी कार्यशैली दिखाने की है। भाजपा और कांग्रेस में जहां टिकट को लेकर दावेदारों की लंबी कतारें और भीतरखाने की खींचतान शुरू हो जाती है, वहीं यूकेडी अपने उम्मीदवारों को पहले ही मैदान में उतारकर उन्हें क्षेत्र में सक्रिय होने का मौका देना चाहता है। अब देखना यह है कि घोषित चेहरे अपने-अपने क्षेत्रों में कितनी राजनीतिक जमीन तैयार कर पाते हैं। यूकेडी की असली सियासी परीक्षा 16 प्रत्याशियों की सूची से आगे शुरू होती है। पार्टी 14 क्षेत्रीय दलों और संगठनों को एक मंच पर लाने की कोशिश में जुटी है। देहरादून में आयोजित मंथन 2027 क्षेत्रीय एकता से उत्तराखंड का राजनीतिक विकल्प कार्यक्रम इसी रणनीति का हिस्सा है। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, स्वाभिमान मोर्चा, राष्ट्रीय रीजनल पार्टी, समानता पार्टी, हिमालय क्रांति पार्टी, विकास पार्टी और राज्य आंदोलनकारी मंच सहित विभिन्न संगठनों की भागीदारी ने तीसरे मोर्चे की चर्चा को हवा दी है।

यहां यूकेडी का दांव केवल चुनाव लड़ने का नहीं, बल्कि क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर बिखरे राजनीतिक समूहों को एक छत के नीचे लाने का है। पार्टी जानती है कि अकेले दम पर भाजपा और कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे को चुनौती देना आसान नहीं है। लेकिन यदि क्षेत्रीय दलों और संगठनों के वोट एक जगह जुट गए तो कई सीटों पर चुनावी तस्वीर बदल सकती है।

यूकेडी के सामने सबसे बड़ा सवाल उसकी अपनी राजनीतिक विरासत का है। जिस दल के आंदोलन ने उत्तराखंड राज्य की नींव रखी, वह राज्य गठन के बाद सत्ता की राजनीति में लगातार कमजोर क्यों होता चला गया? जनता के बीच यह सवाल आज भी मौजूद है। राज्य आंदोलन की भावनाओं को राजनीतिक ताकत में बदलने के बजाय क्षेत्रीय राजनीति का बिखराव राष्ट्रीय दलों के लिए अवसर बनता रहा। अब यूकेडी फिर उसी भावनात्मक पूंजी को राजनीतिक पूंजी में बदलना चाहता है। गैरसैंण राजधानी, पहाड़ों से पलायन, बेरोजगारी, जमीनों की खरीद-फरोख्त, जल-जंगल-जमीन पर अधिकार, बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा जैसे मुद्दे उसके एजेंडे में हैं। लेकिन केवल इन मुद्दों को उठाने से चुनाव नहीं जीते जाते। जनता को यह भरोसा भी देना होगा कि क्षेत्रीय दल सत्ता में आया तो वह राष्ट्रीय दलों से अलग क्या करेगा और कैसे करेगा।

आर्थिक विकास में आत्मनिर्भर भारत की भूमिका पर छात्रों ने रखे विचार



संवाददाता

देहरादून। सरदार महिपाल राजेन्द्र जनजातीय पीजी कॉलेज, साहिया में अर्थशास्त्र विभाग के तत्वावधान में आत्मनिर्भर भारत: आर्थिक विकास की दिशा विषय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

सरदार महिपाल राजेन्द्र जनजातीय पीजी कॉलेज, साहिया में अर्थशास्त्र विभाग के तत्वावधान में विभागीय गतिविधि कार्यक्रम के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत: आर्थिक विकास की दिशा विषय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। प्रतिभागियों ने आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा, स्वदेशी उत्पादन, रोजगार सृजन, उद्यमिता, कौशल विकास, तकनीकी नवाचार एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में आत्मनिर्भरता की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। छात्रों ने विषय के पक्ष एवं विपक्ष में प्रभावशाली तर्क प्रस्तुत करते हुए आत्मनिर्भर भारत की संभावनाओं एवं चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला।

प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर बीए पंचम सेमेस्टर की राधि का तोमर ने प्रथम स्थान, बीए तृतीय सेमेस्टर की कशिश तोमर ने द्वितीय स्थान और बीए तृतीय सेमेस्टर की मानसी तोमर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता के समापन पर सभी विजेता छात्राओं को प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष वरुण प्रसाद सेमवाल ने विजेता छात्राओं को बधाई एवं शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि इस प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियाँ छात्रों में विषयगत समझ, तार्किक क्षमता, आत्मविश्वास एवं नेतृत्व कौशल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना नहीं, बल्कि देश में रोजगार के अवसरों का विस्तार, घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन, उद्यमिता का विकास, तकनीकी नवाचार तथा समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर कशिश तोमर, मानसी, रितिका, सोनल, राधिका,अंशिका आदी छात्र-छात्राए उपस्थित रहे।

देवभूमि को बनाएंगे देश की सांस्कृतिक राजधानी, भाजपा ने रखा 65 पार का लक्ष्य: अमित शाह

देहरादून। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड को लेकर भाजपा का बड़ा राजनीतिक और सांस्कृतिक एजेंडा सामने रखते हुए कहा कि पार्टी देवभूमि को देश की सांस्कृतिक राजधानी बनाना चाहती है। परेड ग्राउंड में आयोजित जनसभा से उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को 65 पार का लक्ष्य दिया। साथ ही कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड केवल एक भौगोलिक प्रदेश नहीं, बल्कि देश की आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। भाजपा इसे देश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की वकालत करने लगती है। इसके विपरीत भाजपा सरकार देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान और मूल स्वरूप को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

गृह मंत्री ने प्रदेश में अवैध मजारों और मदरसों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा सरकार अवैध निर्माणों को हटाने का काम जारी रखेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी राहुल गांधी को पसंद नहीं आती। शाह ने कहा कि सरकार कानून के अनुसार अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रतिबद्ध है।

अमित शाह ने बांधे धामी की तारीफों के पुल, सुनाया एक लाख करोड़ के निवेश का किस्सा

देहरादून। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर सराहना की। परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में शाह ने प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों और निवेश की संभावनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री धामी की कार्यशैली का एक दिलचस्प किस्सा भी साझा किया।

अमित शाह ने बताया कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में एक लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा था, तब उन्हें इस आंकड़े पर थोड़ा संदेह हुआ था। उन्हें लगा कि क्या वास्तव में उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में इतने बड़े निवेश का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है?शाह ने कहा कि इस लक्ष्य की वास्तविकता जानने के लिए उन्होंने स्वयं प्रदेश के मुख्य सचिव को फोन किया और निवेश के आंकड़े की पुष्टि की। मुख्य सचिव ने जब उन्हें निवेश योजना की पूरी रूपरेखा समझाई और आंकड़ों की पुष्टि की तो उनका संदेह दूर हो गया। गृह मंत्री ने कहा कि इसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री धामी की कार्यकुशलता और प्रदेश के विकास को लेकर उनकी गंभीरता पर पूरा भरोसा हो गया। अमित शाह की इस टिप्पणी को मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व और निवेश के मोर्चे पर राज्य सरकार की उपलब्धियों के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक सराहना के रूप में देखा जा रहा है।

अंकिता पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस जेनी और तंदूर कांड पर क्यों मौनः धामी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। परेड ग्राउंड में केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम से पहले अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने जेनी प्रकरण और तंदूर कांड का जिक्र करते हुए कांग्रेस की राजनीतिक मंशा पर सवाल खड़े किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषियों को उम्रकैद की सजा दिलाने वाली सरकार से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपने शासनकाल से जुड़े जेनी प्रकरण और तंदूर कांड पर चुप्पी साध लेती है। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस को अंकिता के मामले में तो जवाब चाहिए, लेकिन जेनी प्रकरण और तंदूर कांड पर वह जवाब देने से क्यों बचती है?धामी ने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सरकार ने कार्रवाई की और दोषियों को सजा मिली। इसके बावजूद कांग्रेस इस संवेदनशील मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाने में जुटी है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर दोहरे राजनीतिक मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपने अतीत का भी जवाब देना चाहिए।मुख्यमंत्री के इस बयान से एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति में अंकिता भंडारी हत्याकांड के साथ जेनी प्रकरण और तंदूर कांड को लेकर सियासी बहस तेज होने के आसार हैं।

राहुल गांधी के दौरे पर धामी का तंज, बोले- छात्रों की नहीं, झूठ की गूंज थी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता अब समझ चुकी है कि कांग्रेस के युवराज और उनके नेता किस तरह जनता के बीच भ्रम फैलाकर अपनी राजनीतिक जरूरतें पूरी करना चाहते हैं।मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे का जिक्र करते हुए तंज कसा कि यहां उन्होंने छात्रों की गूंज नहीं, बल्कि श्झूठ की गूंजश् का कार्यक्रम किया। धामी ने कहा कि कांग्रेस युवाओं को गुमराह करने की राजनीति कर रही है, जबकि प्रदेश सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने देश के सबसे सख्त नकलरोधी कानूनों में शामिल कानून बनाया है। इसके परिणामस्वरूप भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है और प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियों में अवसर मिल रहे हैं।मदरसा बोर्ड के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक विकास प्राधिकरण बनाया है। इसका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में समानता लाना और सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है।धामी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह विकास और जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने के बजाय भ्रम और झूठ के सहारे राजनीति करना चाहती है।

आपदा प्रबंधन पर तीन दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ

संवाददाता

रुद्रपुर। सरदार भगतसिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रुद्रपुर में रोवर रेंजर , राष्ट्रीय सेवा योजना एवं 15वीं वाहिनी, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सँयुक्त तत्वावधान में तीन दिवसीय आपदा प्रबंधन कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के संयोजक डॉ बसुन्धरा उपाध्याय एवं डॉ रविन्द्र कुमार ने सयुंक्त तत्वावधान में किया गया।



उन्होंने बताया कि महानिदेशालय राष्ट्रीय आपदा मोचन बल द्वारा वर्ष 2026 को ल्मंत वि ब्बंबपजल ठनपसकपदह घोषित किया गया है, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक छात्र छात्राओं और देशवासियों को प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के प्रति जागरूक करना एवं आपदा के समय स्वयं की जान बचाने तथा प्रभावित आम जनमानस की मदद हेतु प्रशिक्षित करना है।

इस प्रशिक्षण से विद्यार्थियों को आपदाओं के प्रति जागरूक एवं सजग बनाने के उद्देश्य से आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियों, सुरक्षा उपायों तथा आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवायी के प्रति प्रशिक्षित करना था।

इस अवसर पर महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों एवं प्रभारियों के माध्यम से विद्यार्थियों को कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को भूकंप, बाढ़, आगजनी एवं अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में स्वयं की तथा दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।

कार्यक्रम में विद्यार्थियों को बताया गया कि आपदा के समय घबराने के बजाय धैर्य, सूझबूझ और सामूहिक सहयोग से परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। आपदा प्रबंधन केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का सामाजिक एवं नैतिक दायित्व भी है।

महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अवधेश नारायण सिंह ने विद्यार्थियों से ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन का ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक है, क्योंकि जागरूकता और प्रशिक्षण के माध्यम से संकट के समय बहुमूल्य जीवन की रक्षा की जा सकती है।

कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राध्यापकगण, विभाग प्रभारी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने सहभागिता की। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता, आत्मविश्वास, सहयोग एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना रहा। बच्चों ने बहुत रोचकता के साथ प्रश्नोत्तरी करके आपदा प्रबंधन के विषय मे विस्तृत जानकारी ली। कार्यशाला का आयोजन 15 वीं वाहिनी इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार के नेतृत्व में किया गया।आपदा प्रबंधन कार्यशाला में प्रो0 दीपा वर्मा,प्रो अमिता चौरसिया, प्रो सर्वजीत , प्रो0विकास दुबे,डॉ खान ,डॉ मोनू बाला,डॉ प्रदीप,डॉ दुर्गेश शुक्ला,डॉ रवीश त्रिपाठी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद रोवर प्रभारी डॉ रविन्द्र कुमार ने किया।

भालू प्रभावित गांवों में बांटी जा रही है सीटियां!

रुद्रप्रयाग(आरएनएस)। ठंड बढ़ने के साथ वन्यजीवों की सक्रियता को देखते हुए वन विभाग ने ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसके तहत भालू प्रभावित गांवों में सीटियां बांटी जा रही है। साथ ही बीस हजार सीटियां को अतिरिक्त मंगाया गया है। गुलदार के हमलों से बचाव के लिए ग्रामीणों को मुखौटे दिए जा रहे हैं।

जखोली एसडीओ दिवाकर पुंडीर ने बताया कि पिछले वर्ष भालू की अधिक गतिविधि वाले और इस साल भी वन्यजीवों की सक्रियता वाले गांवों में सीटियां बांटी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक भुनाल ग्राम, बक्सीर और पद्मखाल बीट उत्तरी जखोली रेंज में खेतों में काम करने वाली महिलाओं एवं अन्य ग्रामीणों को मास्क और सीटी वितरित की गई है।

उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भी विभाग ने इसका इस्तेमाल किया था और इस बार इसे व्यापक स्तर पर लागू करने की तैयारी है। एसडीओ ने बताया कि इस वर्ष अच्छी बर्फबारी और ठंड के कारण भालू शीतनिद्रा की ओर बढ़ रहे हैं। इससे जिले में उनकी सक्रियता पिछले साल के मुकाबले अपेक्षाकृत कम देखी गई है।

शब्द सामर्थ्य - 59

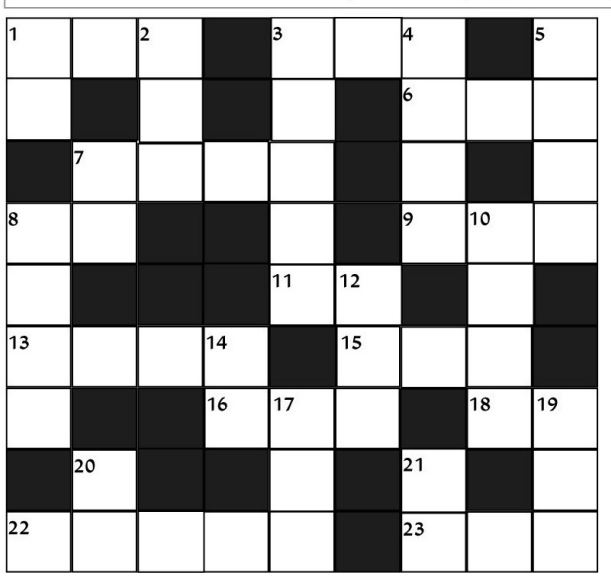
(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. तकलीफ, कष्ट, कठिनाई, परेशानी 3. सरल, सहज 6. ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षा लेना 7. विवश, लाचार 8. अत्यधिक ठंडा, सुस्त 9. अच्छे ढंग में गाया जाने वाला सुंदर गीत 11. सूर्य, सूरज 13. वस्त्र आदि धारण कराना 15. अप्रसन्न, नाखुश 16. खिंचाव, आकर्षण शक्ति (उ.) 18. एक रंग, आसमानी रंग 22. सेवा-सत्कार, आवभगत 23. सर्प, सांप, लकड़ी आदि की मूर्ति बनाना।

ऊपर से नीचे

1. हृदर, उर 2. शिष्टता, भद्रता, विवेक (उ.) 3. अंततः, अंततोगत्वा 4. अच्छी शिक्षा, नेक सलाह 5. आवागमन, गमनागमन 7. पुरुष 8. घोड़े की तेज चाल, तेज गति की दौड़ 10. लूटपाट, डकैती 12. बबार्दी, तबाही 14. नासिका, श्वसनइंद्रीय 17. आखेटक, अरेही 19. योग्य, काबिल 20. कामदेव की पत्नी, प्रेम, आनंद 21. रात्रि, निशा।



शब्द सामर्थ्य क्रमांक 58 का हल

चु	स्त		मु		सं	स्था	न	
ग		म	र्दा	न	गी		त	म
ली	प	ना			त	न		
	ना	ना					ज	
मा	ह		रा		सा	ज	न	
न		स	ह	दे	व		म	द
व		म		व	न	ज		ल
ता	क	त	व	र		मी		द
	ल	ल	क		क	र	त	ल

हुशारु 2 फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच बढ़ी उत्सुकता

वर्ष 2018 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म हुशारु' ने दर्शकों के बीच अच्छी सफलता हासिल की थी। युवा दोस्ती और हास्य से भरपूर इस फिल्म में तेजस कंचेरला, तेज कुरापति, दिनेश तेज, अभिनव मेडिशेट्टी, राहुल रामकृष्ण, दक्षा नागरकर, प्रिया वदलामनी, हेमल इंगले और राम्या पसुपुलेटी ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थीं। फिल्म का निर्देशन श्री हर्षा कोनगंती ने किया था। लंबे समय से इसके दूसरे भाग को लेकर चर्चाएं चल रही थीं। अब निर्माताओं ने आधिकारिक रूप से हुशारु 2' की घोषणा कर दी है। निर्माताओं के अनुसार, हुशारु 2' मूल फिल्म की दोस्ती और युवा ऊर्जा को बरकरार रखते हुए एक नई कहानी और बड़े संसार के साथ दर्शकों के सामने आएगी। फिल्म में इस बार रोमांच और हास्य का स्तर पहले से अधिक होने की उम्मीद है। श्री हर्षा कोनगंती लेखक और निर्देशक के रूप में इस कड़ी में वापसी कर रहे हैं। फिल्म के मुख्य अभिनेता के रूप में अशोक गल्ला के नाम की लंबे समय से चर्चा थी। अब आधिकारिक घोषणा के साथ यह भी स्पष्ट हो गया है कि वह फिल्म का हिस्सा हैं। निर्माताओं ने संकेत दिया है कि फिल्म युवाओं के मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए एक अलग और अप्रत्याशित दुनिया पेश करेगी। हुशारु 2' के नाम की घोषणा के साथ जारी पोस्टर ने फिल्म के विषय को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है। पोस्टर में काबूम बीयर' से लदा एक ट्रक एक अनोखे दृश्य में फंसा दिखाई देता है। उसके चारों ओर एक विशाल सांप लिपटा हुआ है, जबकि नीचे कछुआ और सोने से भरा खजाने का संदूक नजर आता है। पृष्ठभूमि में एक कारखाना भी दिखाई दे रहा है। पोस्टर में पांच दोस्तों को इसी विचित्र और रोमांचक माहौल के बीच दिखाया गया है। पूरा दृश्य पौराणिक कथा समुद्र मंथन' की याद दिलाता है। ऐसे में माना जा रहा है कि फिल्म की कहानी में हास्य और रोमांच के साथ पौराणिक संदर्भों का भी दिलचस्प इस्तेमाल किया जा सकता है।



फिल्म में राहुल रामकृष्ण, अशोक गल्ला, रवि एंथनी, दिनेश तेज, शशिधर कोचरलाकोटा, विधि यादव, अभिज्ञा वुथुलुरु, भगवान तिवारी, जतिन गोस्वामी और राजाई रोवन प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का संगीत सनी एमआर ने तैयार किया है, जबकि छायांकन की जिम्मेदारी जी. श्रीनिवास रेड्डी ने संभाली है। फिल्म का निर्माण राहुल वर्मा, के. वीना रानी और के. हनुमंत राजू द्वारा केवमैन स्टोरीज, एचके फिल्म्स और कलियुग वारधा क्रिएशन्स के बैनर तले किया जा रहा है। हुशारु 2' की घोषणा के साथ ही फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ गई है। अब निगाहें फिल्म की कहानी, कलाकारों के किरदार और प्रदर्शन की तारीख से जुड़ी आधिकारिक जानकारी पर टिकी हैं।

अब फरवरी 2027 में रिलीज हो सकती है प्रभास की फिल्म फौजी

साउथ सुपरस्टार प्रभास इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर लगातार चर्चा में हैं। उनके कई बड़े प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, जिनका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इन्हीं में से एक फिल्म है फौजी। हनु राघवपुड़ी के निर्देशन में बन रही इस पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म को लेकर अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मेकर्स एक बार फिर फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। प्रभास की फौजी को पहले 3 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज करने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब खबर है कि फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म अपनी तय रिलीज डेट पर सिनेमाघरों में दस्तक नहीं देगी। दरअसल, दिसंबर के पहले हफ्ते में कई मिड-रेंज फिल्मों ने अपनी रिलीज की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में मेकर्स फौजी की रिलीज को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मेकर्स अब फौजी को फरवरी 2027 में रिलीज करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म की नई रिलीज डेट को लेकर आखिरी फैसला नेटफ्लिक्स के साथ बातचीत के बाद लिया जाएगा। ऐसे में फैंस को फौजी की नई रिलीज डेट के ऑफिशियल डेट का इंतजार करना होगा। फौजी में प्रभास के साथ इमानवी फीमेल लीड रोल में नजर आएंगी।

फिल्म में अनुपम खेर, जया प्रदा, मिथुन चक्रवर्ती और चैत्रा जे. आचार जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। फिल्म के म्यूजिक की जिम्मेदारी विशाल चंद्रशेखर संभाल रहे हैं। इस फिल्म को लेकर प्रभास के फैंस के बीच पहले से ही काफी एक्साइटमेंट है। फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स प्रोड्यूस कर रहा है। फिल्म के निर्देशक हनु राघवपुड़ी हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री व मुख्यमंत्री ने छह बच्चों को राज्य बाल वीरता पुरस्कार से किया सम्मानित

संवाददाता

देहरादून। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के छह बच्चों को प्रथम मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया।



आज यहां केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड, देहरादून में प्रदेश के छह बच्चों को प्रथम मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। विभिन्न परिस्थितियों में अदम्य साहस, वीरता एवं सूझबूझ का परिचय देने वाले इन बच्चों को पदक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को ₹1 हजार की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रथम बार मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इस पुरस्कार के लिए राज्य स्तर पर प्राप्त आवेदनों में से छह बच्चों का चयन किया गया। इनमें जनपद चमोली के तीन तथा चम्पावत, देहरादून एवं टिहरी गढ़वाल के एक-एक बच्चे शामिल हैं।

जनपद चमोली की दिव्या, दीपिका एवं आरव सिंह को भालू के हमले के दौरान साहस एवं सूझबूझ का परिचय देने के लिए सम्मानित किया गया। 22 दिसम्बर 2025 को जीआईसी यूपीएस हरिशंकर, चमोली में प्रात: लगभग 9:30 बजे एक भालू विद्यालय परिसर में घुस आया था। भालू ने कक्षा छह के छात्र आरव सिंह पर हमला कर दिया। आरव ने स्वयं को बचाने के लिए संघर्ष किया, जबकि कक्षा आठ की छात्रा दिव्या ने भालू का पीछा कर आरव को बचाने का प्रयास किया। इस दौरान दिव्या ने आरव को सुरक्षित विद्यालय तक पहुंचाने में सहायता की। वहीं दीपिका ने तत्काल अन्य नौ विद्यार्थियों को कक्षा सात के कमरे में पहुंचाकर सुरक्षित किया। तीनों बच्चों ने विपरीत परिस्थितियों में साहस और सूझबूझ का परिचय दिया। जनपद चम्पावत की कु. माया को नदी के तेज बहाव में फंसी एक बालिका को बचाने के लिए सम्मानित किया गया। 05 अगस्त 2025 को भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया था। एक बालिका तेज धारा में बहने लगी। माया ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने का प्रयास किया और तेज बहाव से सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान माया स्वयं भी घायल हो गई थीं।

उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी साहस का परिचय देते हुए एक बालिका का जीवन बचाया। जनपद देहरादून की कु. आराध्या को बादल फटने की घटना के दौरान साहस एवं सतर्कता दिखाने के लिए सम्मानित किया गया। 02 जून 2026 की संध्या को भारी बारिश के कारण अचानक मलबा और पानी आने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। आराध्या ने खतरे को भांपते हुए घर में मौजूद सभी 17 लोगों को तत्काल सतर्क किया, जिससे वे सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके। इसके साथ ही उन्होंने तीन वर्षीय एक छोटी बच्ची को पानी के तेज बहाव से भी बचाया। उनकी सूझबूझ से एक बड़ी दुर्घटना टल गई। जनपद टिहरी गढ़वाल की कु. श्वेता को एक बुजुर्ग व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए सम्मानित किया गया। 30 जनवरी 2025 को एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क पर लाठी के सहारे चल रहे थे। इसी दौरान सामने से एक वाहन तेजी से आ रहा था। श्वेता ने तत्काल बुजुर्ग का हाथ पकड़कर उन्हें सड़क के किनारे सुरक्षित किया। उनकी तत्परता से बुजुर्ग व्यक्ति की जान बच गई। मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार का उद्देश्य असाधारण साहस, वीरता एवं सूझबूझ का परिचय देने वाले बच्चों को प्रोत्साहित एवं सम्मानित करना है। इस पहल के माध्यम से ऐसे बच्चों के साहसिक कार्यों को पहचान देने के साथ ही अन्य बच्चों को भी कठिन परिस्थितियों में साहस, संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी का परिचय देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

एनएसएस ने जलाए जागरूकता के दीप, लिया नशामुक्ति संकल्प

हमारे संवाददाता

देहरादून। नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के अंतर्गत सरदार महिपाल राजेंद्र जनजातीय (पीजी) कॉलेज, साहिया की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों द्वारा महाविद्यालय के गोद लिए गए गांव ददोली में नशामुक्ति जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वयंसेवियों ने नशामुक्ति दीपोत्सव, रंगोली, संकल्प अभियान एवं सांस्कृतिक नृत्य के माध्यम से ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के चेयरमैन अनिल सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वस्थ एवं नशामुक्त युवा ही विकसित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। उन्होंने युवाओं और ग्रामीणों से नशे से दूर रहने की अपील करते हुए संदेश दिया कि नशे से नाता तोड़ो और जिंदगी व किताबों से नाता जोड़ो। राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी डॉ. प्रियंका जलाल एवं रिंकूदास भारती के नेतृत्व में स्वयंसेवियों और ग्रामीणों को जीवन में कभी भी नशा न करने और समाज को नशामुक्त बनाने की शपथ दिलाई।

धनतेरस पर पुलिस ने लौटाई 82 लोगों के चेहरों की मुस्कान

हमारे संवाददाता

हरिद्वार। धनतेरस और दीपावली के त्योहार के बीच पुलिस ने 82 लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटाई है। कोतवाली कनखल पुलिस ने सीईआईआर पोर्टल और सर्विलांस की मदद से खोए हुए 82 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए। बरामद मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत 12 लाख 30 हजार रुपये बताई गई है।

जानकारी के अनुसार आज कोतवाली कनखल में पुलिस अधीक्षक नगर की उपस्थिति में मोबाइल फोन उनके स्वामियों को सुपुर्द किए गए। लंबे समय से अपने खोए हुए मोबाइल की तलाश कर रहे लोगों के लिए यह किसी दीपावली के तोहफे से कम नहीं रहा। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। कई लोगों ने बताया कि वे मोबाइल मिलने की उम्मीद लगभग छोड़ चुके थे, लेकिन पुलिस के प्रयासों से उन्हें अपने फोन वापस मिल गए। कनखल पुलिस की ओर से मोबाइल बरामदगी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 268 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं। इन सभी मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 40 लाख 20 हजार रुपये है। मोबाइल फोन वापस मिलने पर स्वामियों ने कनखल पुलिस की कार्यशैली और प्रयासों की सराहना करते हुए आभार जताया। पुलिस की इस कार्रवाई ने त्योहार के मौके पर उन लोगों को बड़ी राहत दी, जो अपने कीमती मोबाइल वापस मिलने की उम्मीद छोड़ चुके थे।



संगठन की मजबूती और बूथ सशक्तीकरण पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता : शर्मा

अल्मोड़ा(आरएनएस)।भाजपा के उत्तराखंड प्रदेश संगठन महामंत्री फणींद्रनाथ शर्मा ने कहा कि संगठन की मजबूती और बूथ सशक्तीकरण पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मेरा बूथ सबसे मजबूत और बूथ जीता, चुनाव जीता के मंत्र को धरातल पर साकार करने का आह्वान किया। फणींद्रनाथ शर्मा के प्रथम अल्मोड़ा आगमन पर भाजपा जिला कार्यालय पातालदेवी में विधानसभा अल्मोड़ा और सोमेश्वर के अपेक्षित श्रेणी के पार्टी पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष महेश नयाल ने की। उन्होंने संगठन महामंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में कार्यकर्ता नई ऊर्जा के साथ संगठन को मजबूत करेंगे। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने के संकल्प को भी दोहराया। बैठक को संबोधित करते हुए फणींद्रनाथ शर्मा ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता केवल राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं, बल्कि एक परिवार का हिस्सा है। संगठन की वास्तविक शक्ति उसका समर्पित कार्यकर्ता है और संगठन हमेशा व्यक्ति से ऊपर होता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पिछले विधानसभा चुनाव की गलतियों से सीख लेने और उन्हें दोहराने से बचने की नसीहत दी। कहा कि आगामी चुनाव को लक्ष्य बनाकर अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। इसके लिए मंडल अध्यक्षों को शक्ति केंद्र अध्यक्षों और शक्ति केंद्र अध्यक्षों को बूथ अध्यक्षों के साथ निरंतर संपर्क और संवाद बनाए रखना होगा। सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में लगातार तीन बार जनता का आशीर्वाद मिलने का उल्लेख करते हुए उन्होंने इसे संगठन और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि इस जनसमर्थन को बनाए रखते हुए अल्मोड़ा और सोमेश्वर दोनों विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल करने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को बूथ स्तर पर सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में विजय केवल राजनीतिक लक्ष्य नहीं, बल्कि संगठन की सामूहिक मेहनत, अनुशासन, समर्पण और जनविश्वास की परीक्षा भी है। बैठक में प्रदेश मंत्री गौरव पांडे, महापौर अजय वर्मा, दर्जा राज्य मंत्री गंगा बिष्ट, कुंदन लटवाल, सिकंदर पवार, गोविंद पिलख्वाल, पूर्व विधायक कैलाश शर्मा, किरन पंत, पूर्व जिलाध्यक्ष रवि रौतेला, अरविंद बिष्ट, ललित लटवाल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बिट्टू कर्नाटक, राजीव राज, गिरीश खोलिया, ब्लॉक प्रमुख नीमा आर्या, महिला मोर्चा अध्यक्ष पूनम पालीवाल, जिला पदाधिकारी कृपाल नयाल, संदीप श्रीवास्तव, मनीष जोशी, मनोज जोशी, धर्मेंद्र बिष्ट, कमल बिष्ट, मदन बिष्ट, सौरभ वर्मा, सुनील बिष्ट सहित विभिन्न मंडलों और मोर्चों के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक का संचालन जिला महामंत्री दर्शन रावत और प्रकाश भट्ट ने संयुक्त रूप से किया।

सू- दोकू क्र. 59

		3					7	
9				6		3		8
	7		9		5		6	
						1		9
3		8		7			5	
	1		3		9			7
		2		8		7		
	8				2		4	3
			1					

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र.58 का हल

5	2	4	9	6	7	8	1	3
3	6	7	4	1	8	2	9	5
8	1	9	3	2	5	4	6	7
6	3	5	1	9	4	7	2	8
7	9	8	5	3	2	6	4	1
2	4	1	7	8	6	5	3	9
4	5	3	6	7	9	1	8	2
9	8	6	2	5	1	3	7	4
1	7	2	8	4	3	9	5	6

दिवाली पर उत्तरकाशी में बदली रहेगी यातायात व्यवस्था

नई टिहरी(आरएनएस)। दीपावली पर खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए उत्तरकाशी पुलिस ने शहर की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है।

इस दौरान बाजार क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की जाएगी। लोगों को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर वाहन खड़े कर पैदल बाजार पहुंचना होगा।पुलिस की ओर से जारी यातायात प्लान के अनुसार, धरासू की ओर से आने वाले वाहनों को मनेरा और बड़ेथी बाईपास से डायवर्ट कर जोशियाड़ा स्थित ट्रक यूनियन पार्किंग में खड़ा कराया जाएगा। भटवाड़ी और हर्षिल से आने वाली टैक्सियों को भद्री स्टैंड से आगे नीचे आने की अनुमति नहीं होगी। निजी वाहन संस्कृत महाविद्यालय से भद्री स्टैंड तक निर्धारित स्थानों पर पार्क किए जा सकेंगे।

यातायात का दबाव बढ़ने पर तेखला से वाहनों को इंद्रावती और जोशियाड़ा पार्किंग की ओर भेजा जाएगा। वहीं, देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश की ओर से आने वाले यात्री वाहनों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। गंगोत्री जाने वाले वाहनों के लिए बड़ेथी बाईपास से बैराज तिराहा, एनआईएम बैंड, एमडीएस स्कूल, मानपुर तिराहा और तेखला मार्ग निर्धारित किया गया है। मानपुर-साल्ड रोड से आने वाले वाहन इंद्रावती पार्किंग में, जबकि साल्ड बैंड और ज्ञानसू की ओर से आने वाले वाहन दरबार बैंड पार्किंग में खड़े होंगे।

गोत्री और हर्षिल से आने वाले वाहनों को भी निर्धारित तेखला डायवर्जन रूट से आवागमन करना होगा। ट्रक यूनियन ग्राउंड जोशियाड़ा, इंद्रावती पार्किंग, दरबार बैंड ज्ञानसू और बस अड्डे को पार्किंग स्थल बनाया गया है। भारी वाहनों का बाजार क्षेत्र में सुबह 9 से रात 9 बजे तक प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। रोटेशन बसों और आवश्यक सेवाओं के वाहनों को छूट दी गई है। उत्तरकाशी पुलिस ने वाहन चालकों से निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करने और पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने को कहा है।

शिविर में 341 दिव्यांग हुए लाभान्वित

चमोली(आरएनएस)। जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित दिव्यांग शिविर में 341 दिव्यांगों को लाभ मिला। गौचर के जीआईसी में लगे शिविर में विभिन्न जिलों के दिव्यांगों को सहायता उपकरण प्रदान किए गए। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने आयोजकों को स्मृति चिह्न भेंटकर सम्मानित किया। चिकित्सकीय टीम प्रभारी अनुज लोधी के नेतृत्व में आठ तकनीकी विशेषज्ञों ने दिव्यांगों के शारीरिक अंगों की नाप-जोख की और उन्हें सहायता उपकरण दिए। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति बाड़मेर और जयपुर की ऑर्गेनाइजेशन फॉर हैंडीकैप्ड फुट नी एंड लिंब संस्था ने शिविर में सहयोग किया। चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर और अल्मोड़ा जैसे कई जिलों के दिव्यांगों ने इसका लाभ उठाया। जिलाधिकारी ने कहा कि इस शिविर में दिव्यांगों को 53 कृत्रिम पैर और 8 कृत्रिम हाथ दिए गए। इसके अतिरिक्त, 111 श्रवण यंत्र, 23 बैसाखी और 41 व्हीलचेयर भी दी गईं।

10 ग्रामीण सड़कों की सुधरेगी सेहत, 23 करोड़ की मिली स्वीकृत

नई टिहरी(आरएनएस)। टिहरी जिले में पीएमजीएसवाई से लोनिवि को हस्तांतरित 10 सड़कों के सुधारीकरण, डामरीकरण की राह आसान हो गई। शासन ने इन सड़कों के लिए वन-टाइम सेटलमेंट के तहत 23.02 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। इससे जिले की पांच विधानसभा क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों की स्थिति सुधरने की उम्मीद जगी है। घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह और टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने बताया कि घनसाली विधानसभा क्षेत्र की पिलखी-गौजियाणा-बनचुरी 11 किमी सड़क के सुधारीकरण एवं डामरीकरण के लिए 2.07 करोड़ और ढुंग-खबोगी मार्ग के 1 से 5.500 किमी के बीच 5.29 किमी के नवीनकरण एवं अवशेष निर्माण कार्य के लिए 1.29 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। टिहरी विधानसभा क्षेत्र में बादशाहीथौल-सौंदकोटी-केमवालगांव-लामकोट 8.85 किमी सड़क के लिए 1.43 करोड़, जगेठी-तुंगोली 5.95 किमी के लिए 96 लाख, टिपरी-चाह गडोलिया 14.97 किमी के लिए 3.88 करोड़ और चंबा-धरासू हाईवे से नवागांव तक 6.25 किमी सड़क की मरम्मत के लिए 1.24 करोड़ मंजूर किए गए हैं। धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र के थौलधार ब्लॉक में ज्वारना-कंस्यूड़ 18.500 किमी सड़क के अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए 3.85 करोड़ और थत्यूड़-मराड़ 19.600 किमी सड़क के सुधारीकरण के लिए 4.09 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। वहीं, प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र की खुरमोला-नाग 8.05 किमी सड़क के डामरीकरण के लिए 1.91 करोड़ और नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र की गूलर-नाई-मिंडार्थ 8.870 किमी सड़क के अवशेष कार्य एवं मरम्मत के लिए 2.30 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

कल्याणी-जुणगा मोटर मार्ग पर प्रतिकर भुगतान की मांग

नई टिहरी(आरएनएस)। डुंडा विकासखंड के कल्याणी-जुणगा मोटरमार्ग पर सड़क कटिंग के दशकों बाद भी ग्रामीणों को पूरा प्रतिकर नहीं मिलने का मामला सामने आया है। सड़क पर डामरीकरण और अन्य मरम्मत कार्य शुरू होने के बावजूद ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी भूमि के मुआवजे का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। उन्होंने निर्माण कार्यों में मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए विभाग से जवाब मांगा है।ग्रामीणों का कहना है कि कल्याणी-जुणगा मोटरमार्ग की कटिंग करीब 30 से 35 वर्ष पहले शुरू हुई थी। उस समय सड़क लोक निर्माण विभाग के अधीन थी। बाद में सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को हस्तांतरित कर दी गई। वर्तमान में सड़क पर डामरीकरण, सुरक्षा दीवार निर्माण और मरम्मत कार्य की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था एनपीसीसी को सौंपी गई है।

करीब 14 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से ये कार्य कराए जा रहे हैं। जुणगा के पूर्व प्रधान नवीन भंडारी, कुलवीर भंडारी और राजेंद्र भंडारी सहित अन्य ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण के दौरान उनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया, लेकिन सभी प्रभावितों को अब तक पूरा प्रतिकर नहीं मिला है। ग्रामीणों ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाते हुए मानकों के अनुरूप काम कराने की मांग की है।

वहीं, एनपीसीसी के सहायक अभियंता आलोक सिंह ने ग्रामीणों के आरोपों पर बताया कि करीब 30 वर्ष पूर्व 90 प्रतिशत ग्रामीणों को प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है। इसका उल्लेख सरकारी अभिलेखों में भी दर्ज है। उन्होंने बताया कि पटवारी की मौजूदगी में मौके पर नापजोख के आधार पर ग्रामीणों को स्थिति समझाई गई। करीब नौ किलोमीटर सड़क पर डामरीकरण व अन्य मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। एक साल की अवधि तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य है।

कल्प केदार मंदिर परिसर की दीवारों का ऊपरी भाग दिखने लगा

नई टिहरी (आरएनएस)। गत वर्ष धराली आपदा के दौरान मलबे में दबे प्राचीन कल्प केदार मंदिर को ढूंढने के लिए की जा रही खोदाई में इसकी तीन ओर की दीवारों का ऊपरी हिस्सा दिखने लगा है लेकिन अभी तक मुख्य मंदिर के किसी प्रकार के निशान वहां पर नहीं मिल पाए हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि वहां पर दो बोल्डर आए हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन पत्थरों के नीचे ही मंदिर का मुख्य भाग दबा है।गत वर्ष अगस्त में धराली की खीर गंगा में आई आपदा के दौरान प्राचीन कल्प केदार मंदिर भी करीब 20 से 25 फीट मलबे के नीचे दब गया था। आपदा के बाद खोज-बचाव अभियान चला रही एनडीआरएफ की टीम की मदद से ग्रामीणों ने उसकी लोकेशन तलाश कर वहां पर हनुमान झंडे की स्थापना की थी लेकिन स्थानीय समेश्वर देवता के आदेश पर वहां पर मंदिर ढूंढने के लिए प्रयास नहीं किए गए।इस वर्ष ग्रामीणों ने आराध्य देवता के आदेश पर नवरात्रि के पहले दिन वहां पर जेसीबी से खोदाई शुरू की थी। ग्राम प्रधान अजय नेगी ने बताया कि खोदाई के 24 दिन बाद वहां पर मंदिर परिसर की तीन ओर की दीवारों का ऊपरी हिस्सा दिख रहा है लेकिन अभी मुख्य मंदिर का कुछ पता नहीं चल पा रहा है।

वहां पर दो बोल्डर आपदा के दौरान बह कर आए थे। वे करीब एक मंजिल ऊंचे हैं। इसलिए स्थिति को देखकर यही लग रहा है कि मंदिर का मुख्य भाग इन बोल्डरों के नीचे दबा होगा। अब ग्रामीणों को यही उम्मीद है कि जल्द मंदिर के मुख्य भाग के कुछ निशान दिख पाए।

गृह मंत्री अमित शाह के देहरादून आगमन पर कांग्रेस ने जताया विरोध

हमारे संवाददाता

देहरादून। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के देहरादून आगमन पर उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपनी बांह पर काली पट्टी बांध कर विरोध दर्ज किया। उन्होंने भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों, प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग तथा राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही को लेकर अपना विरोध प्रकट किया।

इस अवसर पर मीडिया से रू-ब-रू होते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि उत्तराखण्ड की जनता आज अनेक गंभीर समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन केन्द्र और राज्य की भाजपा सरकारें जनता के सवालों का जवाब देने के बजाय राजनीतिक आयोजनों और प्रचार-प्रसार में व्यस्त हैं। प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखण्ड के स्वाभिमान और बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा बेहद संवेदनशील मामला है। प्रदेश की जनता आज भी अंकिता को पूर्ण न्याय दिलाने और हत्याकांड से जुड़े तमाम सवालों के निष्पक्ष एवं पारदर्शी समाधान की मांग कर रही है। लेकिन सरकार इन सवालों पर स्पष्ट जवाब देने से बचती रही है। गोदियाल ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। देवभूमि की बेटियों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। महिलाओं के प्रति अपराधों पर प्रभावी रोकथाम, पीड़ितों को न्याय और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराने का उद्देश्य केन्द्र सरकार और भाजपा नेतृत्व को यह संदेश देना है कि उत्तराखण्ड की जनता अपने अधिकारों, सम्मान और न्याय के सवालों पर चुप नहीं बैठेगी। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से जनहित के मुद्दों को उठाती रहेगी तथा प्रदेश की जनता की आवाज बनकर संघर्ष जारी रखेगी।



यूकेडी का 'चौका' भाजपा-कांग्रेस...

◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

कांग्रेस के पास सरकार विरोधी मुद्दे और पुराना राजनीतिक आधार। इनके सामने यूकेडी को अपनी चुनावी उपयोगिता साबित करनी होगी। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या प्रदेश के क्षेत्रीय राजनीतिक संगठनों के बीच कोई व्यापक तालमेल बन पाएगा? यदि ऐसा हुआ तो चुनावी मुकाबले में नया समीकरण पैदा हो सकता है। लेकिन यदि क्षेत्रीय ताकतें अलग-अलग चुनाव लड़ती हैं तो उनका बिखरा जनाधार राष्ट्रीय दलों के लिए ही फायदेमंद साबित हो सकता है। फिलहाल यूकेडी ने चुनावी पिच पर पहला बड़ा शाट खेल दिया है। भाजपा और कांग्रेस के लिए यह संकेत है कि 2027 का मुकाबला केवल दो दलों के बीच सीमित नहीं रहने वाला। अब देखना यह है कि यूकेडी का यह चौका चुनावी जीत की ओर बढ़ता है या फिर शुरुआती उत्साह तक ही सिमटकर रह जाता है। साफ है, यूकेडी ने शंखनाद कर दिया है। अब चुनौती भाजपा-कांग्रेस को आउट करने की नहीं, जनता के दिल में अपनी जगह बनाने की है।

चुनावी जंग को कांग्रेस तैयार, संगठन..

◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

कि प्रदेश में सरकार के खिलाफ कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें लेकर जनता के बीच असंतोष की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पहाड़ों में पलायन, रोजगार की कमी, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की बदहाली, स्थानीय संसाधनों पर अधिकार और महिला सुरक्षा जैसे सवाल आज भी राजनीतिक विमर्श के केंद्र में हैं। अंकिता भंडारी प्रकरण ने भी प्रदेश की राजनीति में संवेदनशील सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस इन मुद्दों पर सरकार को घेर रही है, लेकिन उसे यह भी बताना होगा कि सत्ता में आने पर वह इन समस्याओं का समाधान किस तरह करेगी। जनता अब केवल विरोध नहीं, विकल्प भी देखना चाहती है। कांग्रेस को अपना चुनावी दृष्टिपत्र और विकास का स्पष्ट रोडमैप सामने लाना होगा।

2027 का चुनाव कांग्रेस के लिए केवल सत्ता वापसी का अवसर नहीं, बल्कि उत्तराखंड में अपने राजनीतिक अस्तित्व और संगठनात्मक ताकत को साबित करने की परीक्षा भी है। पार्टी के पास समय है, मुद्दे हैं और अनुभवी नेताओं की कमी भी नहीं है। कमी यदि कहीं दिखाई देती है तो वह है इन तमाम संसाधनों को एकजुट चुनावी ताकत में बदलने की। भाजपा के खिलाफ माहौल होने की उम्मीद करना अलग बात है और उस माहौल को वोट में बदलने की क्षमता रखना अलग। कांग्रेस को यह समझना होगा कि चुनाव केवल देहरादून के राजनीतिक गलियारों में नहीं जीते जाते। जीत उन गांवों, कस्बों और बूथों पर तय होती है, जहां मतदाता अपने उम्मीदवार और पार्टी की मौजूदगी को महसूस करता है। फिलहाल कांग्रेस ने चुनावी जंग की तैयारी का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या उसका संगठन भी इस जंग के लिए तैयार है? सत्ता का सपना देख रही कांग्रेस को पहले अपने संगठन की हकीकत से रूबरू होना होगा। क्योंकि चुनावी मैदान में भाजपा से मुकाबला करने से पहले उसे अपनी अंदरूनी कमजोरियों से मुकाबला करना है।

केंद्रीय गृह मंत्री एवं मुख्यमंत्री ने किया 1475.31 करोड़ की 62 विकास योजनाओं का लोकार्पण

संवाददाता

देहरादून। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1475.31 करोड की 62 योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया।



आज यहां केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 06 से 13 नवम्बर तक आयोजित उत्तराखण्ड राज्योत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत परेड ग्राउंड, देहरादून में 1475.31 करोड़ की 62 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागों की 1073.11 करोड़ की 44 योजनाओं का शिलान्यास तथा 402.20 करोड़ की 18 योजनाओं का लोकार्पण किया। इन योजनाओं से प्रदेश में सड़क, बिजली, पेयजल, शहरी विकास, शिक्षा, पर्यटन एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम के अंतर्गत ऊर्जा विभाग की यूपीसीएल से संबंधित 472.33 करोड़ की 20 योजनाओं का शिलान्यास तथा 77.93 करोड़ की तीन योजनाओं का लोकार्पण किया गया। इन योजनाओं से प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत संबंधी आधारभूत सुविधाओं के विस्तार में सहायता मिलेगी। पेयजल क्षेत्र में पेयजल निगम की 191.17 करोड़ की आठ योजनाओं का शिलान्यास तथा घ82.03 करोड़ की पांच योजनाओं का लोकार्पण किया गया। इसके अतिरिक्त जल संस्थान की 62.30 करोड़ की दो योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इन योजनाओं से पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा आमजन को पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। लोक निर्माण विभाग की 18.78 करोड़ की एक योजना का शिलान्यास तथा 99.68 करोड़ की तीन योजनाओं का लोकार्पण किया गया। शहरी विकास विभाग की 92.25 करोड़ की चार योजनाओं का शिलान्यास एवं 10.95 करोड़ की एक योजना का लोकार्पण किया गया। इनमें आगामी कुम्भ मेला-2027 के दृष्टिगत हरिद्वार में सड़क, पुल एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास से संबंधित कार्य भी शामिल हैं। गृह विभाग की 68.27 करोड़ की दो योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इनमें देहरादून में 31.63 करोड़ की लागत से साइबर उत्कृष्टता केंद्र तथा हल्द्वानी में 36.64 करोड़ की लागत से फायर स्टेशन के आवासीय भवनों का निर्माण शामिल है। इसके अतिरिक्त डेयरी विकास विभाग की 48.21 करोड़ की योजना का शिलान्यास किया गया, जिसके अंतर्गत सितारगंज में मिल्क पाउडर प्लांट, आइसक्रीम प्लांट एवं बेकरी यूनिट का निर्माण किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग की 19.01 करोड़ की योजना के अंतर्गत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि में पीजी ब्लॉक के निर्माण का शिलान्यास किया गया। आवास विभाग की 10.59 करोड़ की एक योजना का शिलान्यास तथा घ12.48 करोड़ की एक योजना का लोकार्पण किया गया। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग की 11.44 करोड़ की एक योजना का शिलान्यास तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग की 57.15 करोड़ की दो योजनाओं का लोकार्पण किया गया। इन योजनाओं से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होने के साथ ही स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, पर्यटन एवं अन्य क्षेत्रों से संबंधित इन विकास कार्यों का लाभ आमजन को मिलेगा।

फर्जी सहायक सुरक्षा आयुक्त गिरफ्तार

संवाददाता

देहरादून। पुलिस ने फर्जी सहायक सुरक्षा आयुक्त गिरफ्तार कर उसके कब्जे से नीली बत्ती लगी आर्टिगा कार व आरपीएफ की पी-कैप बरामद कर ली। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।



मिली जानकारी के अनुसार अपराधियो के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण राज्य मे प्रचलित ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियो को अपने अपने थाना क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए है। जिसके क्रम मे कोतवाली डोईवाला पुलिस व आरपीएफ देहरादून की संयुक्त टीम को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो खुद को आरपीएफ मे वरिष्ठ अधिकारी बता रहा है, जिसकी गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हो रही है, उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए लच्छीवाला फ्लाईओवर के पास रेलवे लाईन के समीप चैकिंग के दौरान आर्टिगा वाहन, जिसमे नीली बत्ती लगी थी व कार के डैशबोर्ड पर आरपीएफ की पीकैप भी रखी थी, उक्त वाहन मे एक संदिग्ध व्यक्ति, जो खुद को आरपीएफ मे सहायक सुरक्षा आयुक्त मुरादाबाद मंडल बताकर चालकों व आने जाने वालो लोगो पर रौब झाड़ते हुए किसी प्रकार की ठगी अथवा फर्जीवाडा करने की फिराक मे प्रतीत हो रहा था, उक्त व्यक्ति से पुलिस द्वारा गहन पूछताछ की गयी तो उसके द्वारा अपना नाम स्मित कुमार पुत्र राजीव शर्मा निवासी: ग्राम शिवाला कला, पोस्ट ऑफिस शिवाला कला, थाना शिवाला कला, जिला बिजनौर (उत्तर प्रदेश) बताया गया। पूछताछ मे उक्त व्यक्ति द्वारा अपने अधिकारी होने के सम्बन्ध मे कोई पहचान पत्र उपलब्ध नही कराया। पुलिस टीम द्वारा मंडल मुख्यालय आरपीएफ से उक्त सम्बन्ध मे जानकारी की तो इस नाम से कोई अधिकारी होना प्रकाश मे आया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने स्वीकार किया कि वह आरपीएफ में नियुक्त अधिकारी नहीं है और कर्जे में डूबे होने के कारण लोगों पर रोब दिखाकर आसानी से पैसा कमाने के लिए फर्जी अधिकारी बनकर घूम रहा था। उक्त व्यक्ति द्वारा किये जा रहे अपराध के दृष्टिगत डोईवाला पुलिस व आरपीएफ टीम द्वारा स्मित कुमार उपरोक्त को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया व नीली बत्ती लगी मारुति सूजुकी अर्टिगा कार को सीज कर कोतवाली डोईवाला पर मुकदमा दर्ज कर उसके अपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है।

मकान का ताला तोड जेवरात चोरी

संवाददाता

देहरादून। चोरों ने मकान का ताला तोड वहां से जेवरात चोरी कर लिये। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार कृष्णा कालोनी गुमानीवाला ऋषिकेश कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि वह परिवार के साथ बाहर गया था। आज जब वह वापस आया तो उसने देखा कि उसके मकान का ताला टूटा हुआ था तथा अन्दर सारा सामान बिखरा हुआ था। चोर उसके यहां से सोने चांदी के जेवरात व चांदी के सिक्के चोरी करके ले गये हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड फिल्म पुरस्कारों को दी मंजूरी

◆नरेन्द्र सिंह नेगी और हेमंत पाण्डेय को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड फिल्म नीति-2024 के अंतर्गत वर्ष 2024 एवं 2025 के लिए चयनित फिल्मों एवं कलाकारों को उत्तराखण्ड फिल्म पुरस्कार प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत उत्तराखण्डी सिनेमा और फिल्म जगत में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कलाकारों, निर्देशकों, निर्माताओं एवं तकनीकी विशेषज्ञों को सम्मानित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार, वर्ष 2024 के लिए प्रसिद्ध लोकगायक एवं गढ़वाली संस्कृति के संवाहक नरेन्द्र सिंह नेगी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वहीं, वर्ष 2025 के लिए प्रसिद्ध अभिनेता हेमंत पाण्डेय को इस सम्मान के लिए चयनित किया गया है। दोनों विभूतियों को 2-2 लाख रूपए की पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया जाएगा।

वर्ष 2024 के लिए उत्तराखंड बोली की फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार गढ़वाली फिल्म 'घपरोल' के निर्माता अजय ढौंडियाल को दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एवं पटकथा लेखक का पुरस्कार घपरोल के लिए सिद्धार्थ शर्मा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कारा एक प्रथा के लिए रमेश रावत, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कारा एक प्रथा के लिए सुश्री शिवानी भंडारी, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार कारा एक प्रथा के लिए अजय सिंह बिष्ट, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जौनसारी फिल्म मेरे गांव की बाट के लिए श्रीमती मधुबाला, सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार मेरे गांव की बाट के लिए अजब सिंह तथा सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर का पुरस्कार घपरोल के लिए विनय चानना को प्रदान किया



जाएगा। वर्ष 2025 के लिए हिंदी फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 'मनु क्या करेगा' के निर्माता शरद मेहरा को प्रदान किया जाएगा। जबकि केसरी चौप्टर-2' को विभिन्न प्रमुख श्रेणियों में सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक करण सिंह त्यागी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अक्षय कुमार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सुश्री अनन्या पाण्डेय, सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखक करण सिंह त्यागी एवं अमृत पाल, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता आर. माधवन तथा सर्वश्रेष्ठ गायक जुबिन नौटियाल चयनित किए गए हैं।

वर्ष 2025 की उत्तराखण्डी बोली की फिल्मों में गढ़वाली फिल्म 'रैबार' को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके निर्माता भगत सिंह सैनी, निर्देशक सुशील उनियाल, पटकथा लेखक भगत सिंह सैनी, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता राजेश नौगाई, सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर धर्मेन्द्र सिंह सिसोदिया को अलग -अलग श्रेणी में चयनित किया गया है। वहीं, गढ़वाली फिल्म 'द्वि होला जब साथ' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनीष डिमरी एवं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सुश्री कल्याणी गंगोला और सर्वश्रेष्ठ गायक श्री विकास भारद्वाज चयनित किए गए हैं ।

उत्तराखण्ड सरकार राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने, स्थानीय कलाकारों को मंच उपलब्ध कराने तथा प्रदेश की समृद्ध लोकसंस्कृति, भाषा, परंपराओं और प्राकृतिक सौंदर्य को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखण्ड की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है और यहां की क्षेत्रीय फिल्मों एवं कलाकारों को प्रोत्साहन देने से स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे।

सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ध्2 लाख, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ध्1.50 लाख तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अभिनेत्री, पटकथा लेखक, सहायक अभिनेता-अभिनेत्री, गायक एवं सिनेमेटोग्राफर के लिए ध्1-1 लाख की पुरस्कार राशि निर्धारित है। साथ ही निर्माता- निर्देशक को स्वर्ण ब्रह्मकमल ओर प्रशस्ति पत्र जबकि अन्य कलाकारों और तकनीशियनों को रजत ब्रह्मकमल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। पुरस्कारों का चयन निर्णायक मंडल की संस्तुति के अनुसार किया गया है।

गुलदार के हमले से 13 वर्षीय किशोर की मौत

❑वन विभाग ने परिजनों को दी 10 लाख की सहायता राशि

हमारे संवाददाता

चम्पावत। लोहाघाट विकासखंड के सुई डुंगरी गांव में 4 नवंबर को गुलदार के हमले से 13 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। बीते रोज प्रभागीय वनाधिकारी ढीनो पुरुषोत्तम और उप जिलाधिकारी लोहाघाट नीतू डांगर ने शोकाकुल परिवार से भेंट कर सांत्वना दी और वन विभाग की ओर से 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि तत्काल प्रदान की। प्रशासन और वन विभाग ने घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। घटना के बाद क्षेत्र में वन्य जीव हमले से सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ कर दिया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी ने बताया कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रशासन और वन विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रभावित क्षेत्र में तुरंत पिंजरा स्थापित कर दिया गया है और लगातार मॉनिटरिंग के लिए वन विभाग का विशेष स्टाफ तैनात किया गया है। गुलदार की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए क्षेत्र में ट्रैप कैमरे और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है तथा शाम के समय गश्त की सीमा और तीव्रता को काफी बढ़ा दिया गया है। वन विभाग ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और रात्रिकालीन समय में विशेष सावधानी बरतें। इस दौरान अध्यक्ष जिला पंचायत आनंद सिंह अधिकारी, उप प्रभागीय वनाधिकारी सुनील कुमार, ग्राम प्रधान सहित ग्रामीण मौजूद रहे।

अंकिता भंडारी को न्याय मिलने तक जारी रहेगा संघर्षः चमोली

हमारे संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को संपूर्ण न्याय दिलाने की मांग को लेकर हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा, जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता। यह केवल एक बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की अस्मिता, मातृशक्ति के सम्मान, पहाड़ के स्वाभिमान और न्याय व्यवस्था पर जनता के विश्वास की लड़ाई है।



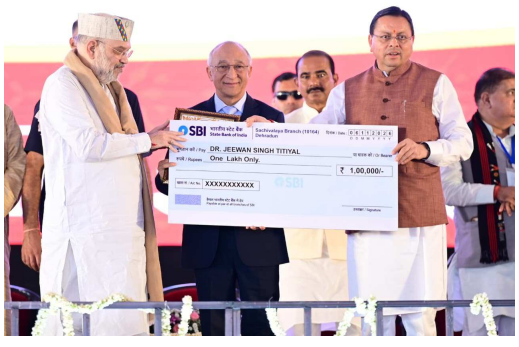
देहरादून घंटाघर में प्रदर्शन के दौरान यह बात आज एडवोकेट संदीप चमोली द्वारा कही गयी। उन्होने कहा कि देश के गृहमंत्री अमित शाह को उत्तराखंड की जनता की भावनाओं और जनआक्रोश को गंभीरता से समझना होगा। उन्हें यह संदेश स्पष्ट रूप से देना होगा कि उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक युवा और प्रत्येक जागरूक व्यक्ति अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना चाहता है। अंकिता के माता-पिता द्वारा उठाई जा रही मांगों और उनकी पीड़ा को संवेदनशीलता के साथ सुना जाना चाहिए। इस मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय जांच तथा दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।

उन्होने कहा कि हमारी मांग है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े प्रत्येक पहलू की निष्पक्ष जांच हो, किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को संरक्षण न मिले और पीड़ित परिवार को न्याय का पूरा भरोसा मिले। न्याय की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव, प्रभाव या पक्षपात स्वीकार नहीं किया जा सकता। आज यदि अपनी आवाज बुलंद करने के कारण हमें गिरफ्तार भी होना पड़े, तो हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। गिरफ्तारी हमारे संकल्प को कमजोर नहीं कर सकती और न ही हमारी आवाज को दबा सकती है। हम लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारों और न्याय की मांग को उठाते रहेंगे। आज एक कदम रोका जा सकता है, लेकिन न्याय की इस लड़ाई को रोकना संभव नहीं है।

15 महानुभावों को किया उत्तराखण्ड गौरव सम्मान पुरस्कार-2026 से सम्मानित

संवाददाता

देहरादून। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड, देहरादून में आयोजित उत्तराखण्ड राज्योत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 15 महानुभावों को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान पुरस्कार-2026 से सम्मानित किया। राज्य के विकास, सामाजिक सेवा, शिक्षा, चिकित्सा, कला, संस्कृति, पर्यावरण, खेल एवं अन्य क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाली विभूतियों को यह सम्मान प्रदान किया गया। उत्तराखण्ड गौरव सम्मान पुरस्कार-2026 के अंतर्गत राजनीतिक एवं शासकीय क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए स्वर्गीय मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉ. जीवन सिंह तितियाल, उद्यमिता के क्षेत्र में मनमोहन भारद्वाज, फिल्म जगत में योगदान के लिए श्रीमती हिमानी शिवपुरी, लोक जागर गायन के क्षेत्र में श्रीमती हेमा नेगी करासी तथा शिक्षा एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए डॉ. गिरीश रंजन तिवारी को सम्मानित किया गया। इसी क्रम में सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सुश्री अनीता थपलियाल शर्मा एवं कश्मीर सिंह, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में पर्यावरणविद् सुरेश भाई तथा लोक गायन के क्षेत्र में श्रीमती रेशमा शाह को



उत्तराखण्ड गौरव सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया। खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा से प्रदेश का नाम रोशन करने वाली सुश्री एकता बिष्ट, सुश्री वंदना कटारिया, सुश्री अंकिता ध्यानी, सुश्री निकिता चंद एवं कपिल पोखरिया को भी उत्तराखण्ड गौरव सम्मान पुरस्कार-2026 से सम्मानित किया गया। उत्तराखण्ड गौरव सम्मान पुरस्कार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियां अर्जित करने तथा समाज एवं प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने की पहल है। इस सम्मान के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली विभूतियों के योगदान को पहचान देने के साथ ही नई पीढ़ी को भी समाज एवं राज्य के विकास में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाता है।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार

समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकारः
वी के अरोड़ा, *एडवोकेट*
बैजनाथ, *एडवोकेट*

कार्यालयः दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।
मो. 9358134808

नोटः सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्री के लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।